ई-1865833

संख्या-08/2024/1115/52-1-2024-03(पी.एम.जे.वी.के.)/2024

प्रेषक,

हरि बख्श सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 04 दिसम्बर, 2024

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता पर पूर्ण की जाने वाली परियोजनाओं की कार्ययोजना के आलोक में निर्माणाधीन परियोजनाओं के सापेक्ष प्राथमिकता पर पूर्ण हो सकने वाली परियोजनाओं की अवशेष धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) SNA से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-3655/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./धन.मांग(330/5) दिनांक 22.11.2024 एवं पत्र सं.-3325/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./धन.मांग(330/5) दिनांक 29.10.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि SNA खाते से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्सम्बन्धी वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की अवशेष धनराशि **रू० 604.605 लाख (रूपये छः करोड़ चार लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि रू० 240.766 लाख (रूपये दो करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार छः सौ मात्र)** अर्थात कुल

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि रू० 845.371 लाख (रूपये आठ करोड़ पैतालीस लाख सैतीस हजार एक सौ मात्र)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न विवरणानुसार SNA पूल फण्ड से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	यूनिट	अनुमोदित लागत	परियोजना हेतु अब तक निर्गत कुल धनराशि (के.+रा.)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि		
							के.	रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अयोध्या	राजकीय आई.टी.आई. का उच्चीकरण	उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम (यू.पी. सिडको)	1	64.360	32.180	19.308	12.872	32.180
2	गाजीपुर	राजकीय बालिका डिग्री कालेज में 200 बेडेड गर्ल्स हास्टल मल्टीपरपज हाल कान्फ्रेन्स हाल	उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम (यू.पी. सिडको)	1	1623.790	568.439	243.456	0.000	243.456
3	प्रतापगढ़	राजकीय डिग्री कालेज गाबी महुआवन	आवास विकास परिषद	1	1078.660	809.000	161.796	107.864	269.660
4	कानपुर नगर	ब्लाक-कानपुर कैण्ट के मीरपुर में कम्युनिटी टायलेट ब्लाक	उ.प्र. राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि.	1	39.350	19.675	11.805	7.870	19.675
5	गोण्डा	बभनजोत में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	उ.प्र. वक्फ विकास निगम	1	140.000	42.000	25.200	16.800	42.000
6	बाराबंकी	सिरौली गौसपुर में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	उ.प्र. वक्फ विकास निगम	1	140.000	84.000	33.600	22.400	56.000
7	कासगंज/एटा	बि.ख. गंजडुण्डवारा में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	उ.प्र. वक्फ विकास निगम	1	140.000	42.000	25.200	16.800	42.000
8	कासगंज/एटा	विकास खण्ड गंजडुण्डवारा गणेशपुर में सदभाव मण्डप का निर्माण	उ.प्र. वक्फ विकास निगम	1	234.000	70.200	42.120	28.080	70.200
9	सम्भल	विकास खण्ड पवासा में सदभाव मण्डप का निर्माण	उ.प्र. वक्फ विकास निगम	1	234.000	70.200	42.120	28.080	70.200
				9	3694.160	1737.694	**604.605**	**240.766**	**845.371**

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- उक्त धनराशि राज्य सरकार के SNA से आहरित कर व्यय किये जाने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(2)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(4)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(5)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. की होगी।

(11)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति न हों।

(12)- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(13)- पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14)- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(15)- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(16)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17)- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(18)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(19)- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(20)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(21)- केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(22)- योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(23)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(24)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(25)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया

http://sfcsandesh.up.gov.in

गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(26)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1115(1)/बावन-1-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि बख्श सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in